[Mr. Chairman]

ner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the Council of the Indian Institute of Science, Bangalore, for the next term commencing from the 1st January, 1978."

The motion was adopted

(ii) TEA BOARD

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG): Sir, I beg to move the following:—

"That in pursuance of sub-section (3)(f) of Section 4 of the Tea Act, 1953 read with rule 4 (1) (b) of the Tea Rules, 1954, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, one member from among themselves to serve as member of the Tea Board, subject to the other provisions of the said Act and the Rules made thereunder, *vice* Shrimati Renuka Devi Barkataki resigned."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That in pursuance of sub-section (3) (f) of Section 4 of the Tea Act, 1953 read with rule 4 (1) (b) of the Tea Rules, 1954, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, one member from among themselves to serve as member of the Tea Board, subject to the other provisions of the said Act and the Rules made thereunder, *vice* Shrimati Renuka Devi Barkataki resigned."

The motion was adopted.

14.14 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) REPORTED CIRCULAR OF MAHARASHTRA GOVERNMENT ABOUT CHARACTER VERIFICATION OF CANDIDATES BELONGING TO CPI(M) AND MARXIST LENINIST BEFORE APPOINTMENT IN GOVERNMENT SERVICE

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Sir, again a very disturbing circular has come in my hands. It is marked 'secret'. The subject written on that is: Infiltration in the State Machinery—Government of Maharashtra, Irrigation Department circular No. MIS-1077/1244-(161)/77-E(3) dated 23rd September, 1977. I will read out the important portions:

"It has been brought to the notice of the State Government that their Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya have observed that the Communist Party of India (Marxist) has mentioned to take an increasing interest in infiltration into the State machinery, particularly, the armed forces and the police."

"The Northern Zonal Committee of the Unity of Centre of Communist Revolutionaries of India (Marxist-Leninist), a Naxalite Organisation also came to notice for directing its cadres to form secret cells in the army and enlist soldiers for a revolutionary struggle."

In the last but one paragraph, it says:

"All the Heads of Department are, therefore directed to note the above observations and to take appropriate preventive and remedial action in the matter at all levels. Further, the acceptance of the prospective candidates should be got discreetly and verified by the police authorities before issue of appointment orders."

"To All Heads of Department, & Officers under Irrigation Department, Mantralya, Bombay...."

The complete list is before me.

This is a very serious matter because it has been directed against two political parties which have legal existence and are not banned organisations. Therefore, these directions and

circulars are illegal and call for the punishment of those who have been the authors of the same. There is also another danger in this, that if such discrimination is shown against some parties today, the same can be done against other parties also. This discreet enquiry envisaged by the Home Ministry can very well mean witch-hunting and the enquiry can be directed against anybody who happens to incur the displeasure of the powers that be. This is most undemocratic and therefore the Government should lay a White Paper on this in the House before the session ends.

I want to lay it on the Table of the House with your permission.

(ii) DEMONSTRATION BY PRIMARY SCHOOL TEACHERS

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : सभापति महोदय, मैं आप की अनुमति से नियम 377 के अन्तर्गत अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा आयोजित एक महाप्रदर्शन की ओर जो प्राथमिक शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने के लिए उनका जो विराट प्रदर्शन हुआ है उसके सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। शायद आप ने अखबारों में देखा और सुना भी होगा कि समूचे देश से लगभग दो लाख प्राथमिक शिक्षक प्रदर्शन में आये हुए हैं। उन्होंने जो अपनी मांगें सरकार के सामने रखी हैं तथा अध्यक्ष, लोक सभा के सामने रखी हैं वह भी मैं आप की अनुमति से सभा-पटल पर रख दूंगा। उन का कहना है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया जाये। वस्तुतः 1956 से जब से महासंघ की स्थापना हुई है, शिक्षा को केन्द्रीय सूची में लाने के लिए वह प्रयत्नशील रहा है। बहुत दिनों के बाद तो मुश्किल से शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया है। उन को इस बात की चिन्ता है कि शायद सरकार समवर्ती सूची से हटाकर शिक्षा को फिर राज्य सूची में लावें। इस बात से शिक्षकों के मन बहुत ही आशंकित और आतंकित हैं क्योंकि राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है। यही कारण है कि आज प्राथमिक शिक्षकों की दशा बड़ी दयनीय है। जब भी कोई मौका लगता है प्राथमिक शिक्षकों के साथ बराबर सौतेले बेटे जैसा व्यवहार होता है। पिछले तीस वर्षों में जब भी कांग्रेस सरकार ने किसी आयोग का गठन किया है तो वह विश्वविद्यालयों अथवा उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में था। 1948 में जो आयोग गठित किया गया वह विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में था, 1949 में टैक्निकल एजूकेशन के सम्बन्ध में था, 1952 में मुदालियर कमीशन की व्यवस्था अथवा स्थापना माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में थी परन्तु आज तक प्राथमिक शिक्षकों अथवा प्राथमिक शिक्षा के लिए एक भी आयोग की स्थापना नहीं की गई। एक सब से बड़ी बात यह है कि हम यह मानते हैं कि निरक्षरता निवारण करना जरूरी है परन्तु आज तीस वर्षों के बाद भी राष्ट्र के लिए यह बड़े शर्म की बात है कि 70 प्रतिशत लोग निरक्षर हैं। आज स्थिति यह है कि जब समूचे शिक्षा के बजट में 1200 करोड़ रुपया होता है बड़े बड़े विश्वविद्यालयों और कालेजों पर खर्च करने के लिए तो प्राथमिक शिक्षा पर केवल साढ़े तीन सौ करोड खर्च हो रहा है। यही कारण है कि संविधान की धारा 45 के अन्दर जब यह कहा गया था कि 14 वर्षों में सब लोगों को साक्षर किया जाये, लेकिन 30 वर्षों के बाद भी संविधान के इस निर्देश का पालन नहीं किया गया है। इसलिए आज समूचे देश से 2 लाख शिक्षक वोट-क्लब पर आये हुए हैं, वहां पर प्रदर्शन और धरना दिए हुए हैं। माननीय सदस्यों और सभापति महोदय को भी आमंत्रण है, कि वे वहां पर जाकर देखें।

सभापति महोदय, शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने में क्यों देर हो रही है ? कहा जाता है कि प्रतिरक्षा को केन्द्रीय सूची में रख सकते हैं, शिक्षा का महत्व उससे कम नहीं है। एडमण्डबर्क ने कहा है—Education is the best defence of a Nation.